बंगाल में डबल इंज़न सरकार से तीव्र विकास होगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया

कोलकाता/जयपुर, 18 अप्रेल। स्वाभिमान और देशभक्ति हर राजस्थानी के मन में समाहित है, यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी बंगाल में एक सभा को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, राजस्थानी देश-दुनिया में कहीं भी चले जाएं, सामाजिक सरोकारों से अपना स्थान बना ही लेते हैं। उन्होंने अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों से गहरा जुड़ाव बनाए रखा है। वे दुनिया के हर हिस्से में अपनी मेहनत, संघर्ष और सफलता से राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं। शर्मा इस समय प.बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानियों की एक सभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के जुड़ाव को और मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 40 चैप्टर्स संचालित हैं।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहले कालीघाट मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। फिर बेलीगंज स्थित गोविन्दम इस्कॉन मंदिर में राधा-कृष्ण के दर्शन किए व पूजा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोलकाता में आयोजित राजस्थान प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले कालीघाट मंदिर और गोविंदम इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कालीघाट मंदिर में विधि-विधान से मां काली की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री कोलकाता के बेलीगंज स्थित गोविंदम इस्कॉन मंदिर पहुंचे और वहां श्री राधा कृष्ण के दर्शन और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ चाय पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना सुनिश्चित है। हम सभी को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में विजयी बनाना है। पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में भी राजस्थान जैसा विकास चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए जुट जाएं। पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में तीव्र विकास होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, ऊर्जा, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र में राजस्थान तेजी से उभर रहा है और यह प्रवासी व स्थानीय उद्योगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि, बिजली, पानी सहित, विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हर जिले में सुचारू आपूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। राइज़िंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर सृजित किए गए हैं।

इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, संयोजक राजस्थान प्रवासी प्रकोष्ठ कुमार लखोटिया, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन पश्चिम बंगाल संतोष कुमार पुरोहित, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव लघु उद्योग भारती नरेश पारीक सहित, बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर आदेश बदला

लखनऊ , 18 अप्रैल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने संबंधी अपने ही आदेश को बदल दिया है। कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर संशोधित आदेश जारी किया।

शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता समेत, केन्द्र और राज्य सरकार के वकीलों से कोर्ट ने पूछा कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है? सभी पक्षों ने नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं बताई। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया था।

- संशोधित आदेश में दोहरी नागरिकता पर एफआईआर से पहले नोटिस देना जरुरी बताया।

हालांकि, आदेश के टाइप होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फैसले की फिर से समीक्षा की।

'विपक्ष ने देश की महिलाओं के सपनों को कुचल दिया'

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने का दोषी विपक्ष को ठहराया

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आज (शनिवार को) देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस अहम मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण, उनकी सियासत में भागीदारी और विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल के समर्थन न किये जाने का जिक्र किया। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सही वक्त का इंतजार कीजिए, आधी आबादी को उनका हक दिलाने का संकल्प जरूर पूरा होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं अपनी बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने नारी हित का प्रस्ताव गिरा दिया। विपक्ष ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया। मैं देश की महिलाओं से माफी मांगता हूं। नारी सबकुछ भूल जाती हैं, लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती है। विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी की नारी हर घटना पर नज़र रख रही है और सच्चाई भी भली-भांति जान रही है।

- प्र.मंत्री मोदी ने कहा कि उनका इरादा पक्का है और महिला आरक्षण की राह में आने वाली हर अड़चन वे दूर करेंगे।

पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है। लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है, दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देशहित को, इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया, वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी।

मोदी ने कहा, नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाया। परिसीमन होता तो सभी राज्यों की सीटें एक अनुपात में बढ़ तीं। वहीं, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विरोधी पार्टी है। सपा ने राममनोहर लोहिया को भुला दिया है। सपा ने लोहिया के सपनों को अपने पैरों तले रौंद दिया। साथ ही, कांग्रेस एंटी-रिफॉर्म पार्टी है। कांग्रेस निगेटिव पॉलिटिक्स करती है।

विपक्ष की एकता ने लोकतंत्र को बचाया

प्रियंका गांधी ने प्रैस वार्ता में यह भी कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की साजिश विपक्ष की एकता से नाकाम हुई है।

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केन्द्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र की रक्षा की है और परिसीमन से जुड़ी साजिश को विफल कर दिया है।

- प्रियंका गांधी ने कहा महिला आरक्षण की आड़ में सरकार परिसीमन में मनमानी करना चाहती थी।

कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून पर तीन साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया और हाल ही में जल्दबाजी में अधिसूचना जारी की। उन्होंने मांग की कि पहले के स्वरूप में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, शुक्रवार को लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। केन्द्र सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढ ांचे में बदलाव की कोशिश की, जिसे विपक्ष ने मिलकर नाकाम कर दिया। यह संविधान और देश की जीत है।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर बिल पास करवाकर परिसीमन में मनमानी करना चाहती थी और जातिगत जनगणना से बचना चाहती थी। उनके अनुसार, यदि बिल पारित होता तो सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताती और यदि नहीं होता तो विपक्ष को महिला विरोधी करार देती।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े कई गंभीर मामलों, उन्नाव, हाथरस, महिला खिलाड़ियों और मणिपुर की घटनाओं में सरकार का रवैया उदासीन रहा है। अब वही सरकार खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है।

प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि परिसीमन और राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता था, जिसमें सरकार को बिना पारदर्शिता के फैसले लेने की छूट मिलती हो।

उन्होंने यह भी कहा कि देश ने देख लिया है कि जब विपक्ष एकजुट होता है, तो केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को चुनौती दी जा सकती है। यही कारण है कि सरकार इस दिन को 'ब्लैक डे' बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत मानता है।

कांग्रेस महासचिव ने अंत में कहा कि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और सरकार की पीआर और मीडियाबाजी को समझ रही हैं।

डीएमके ने अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तुरंत लागू हो, कुल सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और किसी जनगणना या परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना। सरकार के 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विपरीत, जिसने आरक्षण को 15 वर्षों तक सीमित किया था, द्रमुक का बिल आरक्षण को स्थायी बनाने का प्रस्ताव करता है।

द्रमुक ने शुक्रवार को राज्यसभा अध्यक्ष को नियम 267 के तहत नोटिस दिया, जिसमें उस दिन के सत्र को स्थगित कर महिला आरक्षण पर तुरंत चर्चा कराने का अनुरोध किया गया। हालांकि, शुक्रवार को दोनों सदन स्थगित हो जाने के कारण बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने अभी तक द्रमुक के बिल पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके पहले यह तर्क दिया गया था कि सदन की संख्या बढ़ाने से वर्तमान राजनीतिक नेताओं के हित संरक्षित रहेंगे और महिलाओं को अधिक अवसर भी मिलेंगे। विपक्ष के दलों का तर्क है कि परिसीमन के बड़े सवाल हैं, जो राजनीतिक मानचित्र को फिर से आकार देंगे। द्रमुक का दावा है कि विशेष रुप से दक्षिणी राज्य परिसीमन प्रक्रिया में नुकसान में रहेंगे।

'करौली जिला क्रिकेट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीरज के.पवन के समक्ष पहले से ही लंबित थी। परंतु सचिव द्वारा बेहद ही अस्पष्ट और तर्कहीन आदेश पारित किया, जिसके तहत गैरकानूनी तरीके और जल्दबाजी से एसोसिएशन के चुनाव आयोजित कराए जा सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि तत्कालीन खेल सचिव ने करौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों के पक्ष को भी सुनना भी उचित नहीं समझा।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि एडहॉक कमेटी द्वारा दिए गए इलेक्शन आयोजित करने के नोटिस और 6 जून 2025 को खेल सचिव के तर्कहीन आदेश से बचाव करते हुए हाईकोर्ट ने 11 जून को एसोसिएशन को अंतरिम राहत भी दी थी और सचिव के फैसले पर अंतरिम रोक भी लगाई थी।

शनिवार को हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए युवा मामलात और खेल विभाग के नए सचिव को आदेश दिए हैं कि इस मामले पर 60 दिन में तर्कसंगत आदेश पारित करे, परंतु उससे पूर्व सभी पक्षकारों को सुना जाए।

एसआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सजा सभी को देना उचित नहीं है। याचिका में कहा गया कि चयनित एसआई ने कठोर मेहनत से इस परीक्षा को पास किया है और अब इस स्तर पर उन्हें भर्ती से बाहर करना सही नहीं है। चयनित एसआई की एसएलपी पर आगामी दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर भर्ती में चयन से वंचित रहे और भर्ती रद्द करवाने वाले अभ्यर्थियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है, जिससे कि चयनित अभ्यर्थियों की एसएलपी में कोई भी आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष भी सुनेगा।

सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे

पटना, 18 अप्रैल। बिहार विधानसभा का दूसरा सत्र आगामी 24 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र केवल एक दिन का होगा और सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नई सरकार को इसी दिन सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा।

- एक दिन के सत्र के लिये अधिसूचना जारी।

लोकसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया, और राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 2 घंटे 46 मिनट चली।

सोमवार को हो सकती है अमेरिका -ईरान में अगले दौर की वार्ता

पाकिस्तानी सूत्रों ने बताया इस्लामाबाद में हो रही वार्ता के कवरेज के लिए दुनिया भर से मीडियाकर्मी आ रहे हैं।

इस्लामाबाद, 18 अप्रैल। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को खत्म करने के लिए अहम बातचीत का दूसरा दौर इस्लामाबाद में सोमवार को शुरू हो सकता है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के आगमन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब पाकिस्तान सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए शांति बहाली की कोशिशों में जुटा है और हाल ही में सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तेहरान में उच्चस्तरीय बैठकों के जरिए कूटनीतिक प्रयासों को नई दिशा दी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह बातचीत लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस परिणाम दे पाएगी।

तुर्किए की सरकारी संवाद समिति अनादोलू एजेंसी ने पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के आने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी हैं।

- अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि अगर वार्ता सफल रही तो वे भी पाकिस्तान आएंगे।

यह खबर तब आई, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इस हफ़्ते तेहरान में ईरान के प्रमुख अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठकें कीं।

पाकिस्तानी सरकारी सूत्रों ने शनिवार को अनादोलू को बताया कि अमेरिका और ईरान की टीमें सोमवार को ही पाकिस्तान की राजधानी में अपने तकनीकी-स्तर के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का दूसरा दौर शुरू कर सकती हैं।

सूत्रों ने बताया कि दोनों विरोधी पक्षों के वार्ताकार 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत का पहला दौर खत्म होने के बाद से ही, इस्लामाबाद के जरिए एक-दूसरे को संदेश भेज रहे हैं, ताकि बहुप्रतीक्षित बातचीत के अगले चरण की शुरुआत से पहले "अधिकतम सहमति" तक पहुंचा जा सके।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर ने इस हफ़्ते तेहरान में ईरान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ आमने-सामने बातचीत की, जिसके दौरान ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला घोषित कर दिया।

एक पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ इस कार्यक्रम को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों के आने के लिए लॉजिस्टिक इंतज़ाम पहले ही शुरू हो चुके हैं।

'कैसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाथियों की संख्या भी बढती गई। याचिका में कहा गया कि स्पष्ट नियम होने के बावजूद, अनाधिकृत और बाहरी लोग आमेर किले और हाथी गांव के बाहर हाथी सवारी करा रहे हैं। इसके बदले पर्यटकों से पांच हजार से दस हजार रुपए से वसूले जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि उनकी ओर से संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते निर्धारित क्षेत्रों के बाहर हाथी सवारी कराई जा रही है। याचिका में गुहार की गई है कि अवैध हाथी सवारी पर पाबंदी लगाई जाए और अनाधिकृत लोगों को हाथी सवारी कराने से रोका जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिशत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से लगभग 50.46 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 6791.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह निर्णय सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है।

मोजतबा खामनेई ने सेना के नाम संदेश प्रसारित किया

ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा बिजली की तरह हमला करो

तेहरान, 18 अप्रैल। ईरान में आर्मी डे के मौके पर सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने सेना को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए 40 दिन के युद्ध के दौरान सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ईरान की सेना ने दुश्मनों के खिलाफ साहसिक रक्षा की और उन्हें करारा जवाब दिया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद यह उनका पहला आर्मी डे संबोधन था, जिससे इस बयान को और ज्यादा अहम माना जा रहा है।

मोजतबा खामेनेई ने अपने संदेश में कहा कि ईरान की सेना को अब और मजबूत बनाना जरूरी है और उसे बिजली की तरह वार करने की क्षमता हासिल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हालिया युद्ध ने दुश्मनों की कमजोरी और हार को उजागर कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जल्द ही नए कदम उठाए जाएंगे।

सुप्रीम लीडर ने खास तौर पर सेना की तकनीकी ताकत, ड्रोन क्षमता और नौसेना की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि ईरान के ड्रोन दुश्मनों पर बिजली की तरह हमला करते हैं और नौसेना किसी भी समय दुश्मनों को हराने के लिए तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और मजबूत किया जाएगा।

- उन्होंने ईरान -अमेरिका वॉर, जिसमें अभी युद्ध विराम है, पर कहा, हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है यह युद्ध हमारी सेना की ताकत को साबित करता है।

उन्होंने हाल ही में खत्म हुए 40 दिन के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिलकर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह युद्ध 8 अप्रैल को युद्धविराम के साथ खत्म हुआ था। उन्होंने इसे एक बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इसने ईरान की सैन्य ताकत को साबित किया है।

मोजतबा खामेनेई ने इस मौके पर युद्ध में जान गंवाने वाले कमांडरों और सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि इन सैनिकों के बलिदान की वजह से ही देश सुरक्षित है। उन्होंने कई पुराने और हालिया सैन्य नेताओं का नाम लेकर उन्हें याद किया और उनके योगदान को देश के लिए अहम बताया।

बी-टू-बाईपास पर बसी श्रीराम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथ्यों से आदेश प्राप्त किया गया था, ऐसे में उसे रद्द किया जाता है। अदालत ने साल 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई, 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर माना की अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खातेदार सिविल कोर्ट में जमा मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवासन मंडल भी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।

प्रकरण से जुडे अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि साल 1981 में जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति ने खातेदारों से समझौता विक्रय के आधार पर भूमि खरीदने का दावा करते हुए श्रीराम कॉलोनी-बी योजना बनाई। साल 1990 में इस भूमि का अधिग्रहण कर आवासन मंडल को सौंपी गई।

इस दौरान समिति ने जेडीए से नियमितिकरण कराया। इसके बाद पहले चरण का विवाद हाईकोर्ट आने पर अदालत ने साल 2002 में जेडीए को पट्टे जारी करने को कहा और मामला साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ। इस दौरान साल 2019 में आवासन मंडल ने नई याचिका दायर कर कहा कि साल 2002 का आदेश गलत तथ्यों पर आधारित था।

उधर राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने अवाप्तशुदा जमीन का पुन: कब्जा लेने की तैयारियां शुरू कर दी। गत 16 अप्रैल को आवासन मंडल की टीम मौके पर जे.सी.बी. मशीनें और भारी पुलिस जाप्ता लेकर तोड़फोड़ शुरू की। यहां जेसीबी मशीन से जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल, कोठरियां और अन्य अतिक्रमणों के निर्माण को तोडऩा शुरू किया तो वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध जताया और हंगामा कर दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने जेसीबी पर पत्थर फेंक दिए। इससे घबराए हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी थी।

अब श्रीराम कॉलोनी विकास समिति की ओर से दायर अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा तथा जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को होगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

'प्र.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीधे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदाताओं से सीधे बात करने का अवसर दिया गया।

प्रश्न उठता है कि क्या यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या मोदी कंडक्ट ऑफ कंडक्ट?

क्या विपक्ष को जवाब देने का ऐसा ही अवसर मिलेगा?

बहुत कम संभावना है, क्योंकि यह पूरी तरह मोदी शो है।

यह भाषण झूठ, असत्य, अतिशयोक्ति और भाजपा को "पवित्र" और विपक्ष को "दुष्ट" के रूप में पेश करने के प्रयास से भरा था। आम धारणा यह है कि संसद में पहली बड़ी पराजय मिलने के बाद मोदी फिसल रहे हैं।

और उनके भाषण में सबसे ज्यादा ज़हर कांग्रेस पार्टी के लिए आरक्षित है।

ईरान में भी नेतृत्व में "पावर स्ट्रगल" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये मतभेद शायद कठोर रुख वाले आईआरजीसी और अयातुल्लाह के कट्टर समर्थकों तथा अधिक प्रगतिशील वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष को दर्शाते हैं।

शुक्रवार को, विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने घोषणा की थी कि युद्धविराम अवधि के दौरान स्ट्रेट पूरी तरह से वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है।

हालांकि, इसके बाद, अर्ध-सरकारी फ़ारे न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने के कारण स्ट्रेट बंद किया जा रहा है।

ईरानी कमांड संरचना में स्पष्ट रूप से मतभेद हैं और एक पक्ष को नहीं पता कि दूसरा क्या योजना बना रहा है या कर रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि परमाणु रणनीति से लेकर होर्मुज़ स्ट्रेट तक के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ईरानी रुख अस्पष्ट हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भ्रमित करने वाले बयानों और प्रमुख मुद्दों पर बार-बार रुख बदलने से भी स्थिति जटिल हो गई है।

बढ़ते भ्रम में, मैदान पर तैनात सैन्य बल शायद स्थिति की अपनी समझ के अनुसार कार्य कर रहे हैं। स्थिति और गंभीर हो गई है, क्योंकि पूरी ईरानी कमांड संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है और ज़मीनी स्तर के कमांडरों को कार्य करने की बहुत स्वतंत्रता है।

इस प्रकार, ज़मीनी स्तर पर, सैन्य बलों और आईआरजीसी ने अपनी कार्यवाही जारी रखी, जबकि उच्च स्तर पर नेता सैन्य कार्रवाई को धीमा करने या पूरी तरह रोकने पर सहमत हो गए थे।

जहाँ ईरानियों ने पहले होर्मुज़ स्ट्रेट को वाणिज्यिक यातायात के लिए खुला घोषित किया था, वहीं, जब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा यह खुलासा किया गया कि अमेरिकी अभी भी ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को रोक रहे हैं, तो रुख बदल गया और होर्मुज़ को बंद कर दिया गया।

इन जलमार्गों पर गश्त करने वाले ईरानी गनबोट्स ने उन जहाजों पर गोलीबारी की, जो स्ट्रेट से गुजरने और ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से एक सुपर-टैंकर भारतीय झंडे वाला था और उस पर भी गोलीबारी हुई, जिसके बाद जहाज वापस मुड़ गया।

भारतीय जहाज, सैनमार हेराल्ड, तेल लेकर, भारत की ओर जा रहा था और अचानक गोलीबारी से चौंक गया। अब तक, भारतीय जहाजों को युद्धविराम के चरम समय में भी स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की सुविधा मिली हुई थी। एक अन्य भारतीय जहाज, जग अर्नब, को भी आईआरजीसी गार्ड्स द्वारा वापस लौटने का आदेश दिया गया था।

घटना के बाद, यह खबर आई कि भारत के विदेश कार्यालय ने ईरान के भारत स्थित राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। यह नहीं पता कि ईरानी विदेश मंत्रालय और सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी।

टी.एस. एलियट ने 1923 में यह लिखा था, अप्रैल साल का सबसे क्रूर महीना होता है। यह बात अप्रैल 2026 में अत्यधिक साकार हो रही है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908